

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-०९/०८/१९

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹859.48760 लाख (आठ करोड़ उनसठ लाख अड़तालीस हजार सात सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹859.48760 लाख (आठ करोड़ उनसठ लाख अड़तालीस हजार सात सौ साठ रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	स्वीकृत की जाने वाली राशि
1	2	3	4
1	नालंदा	बिहारशरीफ नगर निगम	1,36,99,252.00
2	गया	गया नगर निगम	2,18,48,028.00
3	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम	1,63,34,972.00
4	दरभंगा	दरभंगा नगर निगम	1,36,42,615.00
5	कटिहार	कटिहार नगर निगम	1,10,98,741.00
6	सारण	छपरा, नगर निगम	93,25,152.00
		कुल योग	8,59,48,760.00

कुल स्वीकृत राशि ₹859.48760 लाख (आठ करोड़ उनसठ लाख अड़तालीस हजार सात सौ साठ रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹859.48760 लाख (आठ करोड़ उनसठ लाख अड़तालीस हजार सात सौ साठ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 687, दिनांक- 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगमों के PL खाता में

५

CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

3. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹859.48760 लाख (आठ करोड़ उनसठ लाख अड़तालीस हजार सात सौ साठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0016-पेशाकर के आलोक में अनुदान, विषय शीर्ष- 0016.31.04-सहायक अनुदान वेतन, विपत्र कोड- 48-2217801910016, से की जायगी। इस राशि का व्यय राज्य के सभी नगर निगमों में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि पर किया जायेगा।

6. बिहार पेशाकर व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 16 के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से स्थानीय प्राधिकार द्वारा पेशाकर का उदग्रहण नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 निरस्त हो गई है तथा पेशाकर नगर निकाय का आंतरिक संसाधन नहीं रह गया है।

7. पेशाकर मद में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि का व्यय राज्य के सभी नगर निगमों द्वारा वेतन मद में किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि०(2), दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. सहायक अनुदान की उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 02.07.2019 के मद संख्या- 10 के रूप में प्राप्त है।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/विविध (पेशाकर)-21-07/2014 के पृष्ठ सं०- 175 /टि० पर दिनांक- 02-8-19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 176 /टि० पर दिनांक- 02-8-19 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

07.08.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध (पेशाकर)-21-07/2014 SD /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-07/08/19

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश, विभागीय आई०टी० प्रबंधक, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने संबंधित एवं सभी को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.08.19

सरकार के विशेष सचिव।